रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022023-243416
CG-DL-E-03022023-243416

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2023/माघ 14, 1944
No. 44] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2023/MAGHA 14, 1944

विदेश मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 3 फ़रवरी, 2023

फा. सं. यूआई/352/25/2022.—भारत के राष्ट्रपति एतद्द्वारा इस आदेश के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मानवाधिकारों संबंधी अंतर-मंत्रालयी समिति के गठन के लिए अपनी संस्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसमें *पदेन* क्षमता में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे: :

i. सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय, सह-अध्यक्ष

ii. विशेष सचिव, गृह मंत्रालय, सह-अध्यक्ष

iii. संयुक्त सचिव, यूएनईएस प्रभाग, **विदेश मंत्रालय, सदस्य सचिव**;

iv. संयुक्त सचिव, आईएस-2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, **सदस्य;**

v. संयुक्त सचिव (महिला अधिकारों से संबंधित), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, **सदस्य;**

vi. संयुक्त सचिव (बाल अधिकारों से संबंधित), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, **सदस्य;**

vii. संयुक्त सचिव, **सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सदस्य;**

viii. संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, **सदस्य;**

ix. संयुक्त सचिव, **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सदस्य;**

x. संयुक्त सचिव, **जनजातीय कार्य मंत्रालय, सदस्य;**

xi. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सदस्य;

xii. संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सदस्य;

xiii. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सदस्य;

xiv. संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, सदस्य;

xv. संयुक्त सचिव, **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सदस्य;**

xvi. संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, सदस्य**;**

xvii. संयुक्त सचिव, विधि **कार्य विभाग, सदस्य;**

xviii. संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सदस्य; और

xix. संयुक्त सचिव, नीति आयोग, सदस्य।

2. ऊपर उल्लिखित सदस्यों के अलावा, यह समिति आवश्यकतानुसार मंत्रालयों/विभागों से अतिरिक्त सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

3. समिति निम्नलिखित पर विचार-विमर्श करने और निरीक्षण करने के अधिदेश के साथ कार्यान्वयन, रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी राष्ट्रीय तंत्र के रूप में कार्य करेगी :

i. संधि निकायों के लिए सभी मानवाधिकार रिपोर्टिंग दायित्व, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा और विशेष प्रक्रियाएँ;

ii. उनकी सिफारिशों का कार्यान्वयन; और

iii. राष्ट्रीय हितधारकों के साथ जुड़ाव के तौर-तरीके।

4. समिति वर्ष में दो बार, और जब भी आवश्यक हो, बैठक करेगी। समिति/सदस्य सचिव बैठक का स्थान, तिथि, समय और अवधि तय करेंगे।

5. यह संकल्प गृह मंत्रालय के दिनांक 03 नवंबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1501/86/2022-एचआर-III के माध्यम से उनकी सहमति से जारी किया गया है।

श्रीनिवास गोटू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd February, 2023

F. No. UI/352/25/2022.—The sanction of the President of India is hereby accorded to the constitution of the Inter-Ministerial Committee on Human Rights, from the date of publication of this Order in the Official Gazette, consisting of the following, in their *ex officio* capacity:

i. Secretary (West), Ministry of External Affairs, Co-Chairperson

ii. Special Secretary, Ministry of Home Affairs, Co-Chairperson

iii. Joint Secretary, UNES Division, Ministry of External Affairs, Member Secretary;

iv. Joint Secretary, IS-2 Division, Ministry of Home Affairs, Member;

v. Joint Secretary (dealing with rights of women), Ministry of Women & Child Development, Member;

vi. Joint Secretary (dealing with rights of child), Ministry of Women & Child Development, Member;

vii. Joint Secretary, Department of Social Justice & Empowerment, Member;

viii. Joint Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Member;

ix. Joint Secretary, Ministry of Minority Affairs, Member;

x. Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Member;

xi. Joint Secretary, Ministry of Rural Development, Member;

xii. Joint Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Member;

xiii. Joint Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Member;

xiv. Joint Secretary, Department of Food & Public Distribution, Member;

xv. Joint Secretary, Ministry of Labour & Employment, Member;

xvi. Joint Secretary, Department of School Education & Literacy, Member.

xvii. Joint Secretary, Department of Legal Affairs, Member;

xviii. Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Member; and

xix. Joint Secretary, Niti Aayog, Member.

2. In addition to the members specified above, the Committee may invite additional members from Ministries/Departments to participate in the meetings of the Committee, as and when required.

3. The Committee shall function as the national mechanism for implementation, reporting and follow-up with the mandate to deliberate upon and oversee the following:

i. All human rights reporting obligations to the treaty bodies, the universal periodic review and the special procedures;

ii. Implementation of their recommendations; and

iii. Modalities for engagement with national stakeholders

4. The Committee shall meet twice a year, and as and when required. The Committee/Member Secretary may decide the venue, date, time and duration of the meeting.

5. This resolution issues with the concurrence of the Ministry of Home Affairs, vide their OM No. 1501/86/2022-HR-III, dated 03 November 2022.

SRINIVAS GOTRU, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA